How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

भारत में कृषि नीति व कृषिकों की चुनौतियां का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 राजेश कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र
जी0डी0 बिनानी पी0जी0 कालेज, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश

Email- 1961drs111@gmail.com

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। सन् 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों (जैसे वानिकी) का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 16.6% था। उस समय सम्पूर्ण कार्य करने वाले श्रम का भाग 51% कृषि में लगा हुआ था। राष्ट्रीय कृषि नीति से आ''ाय् सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न आधारभूत सिद्धान्तों तथा विभिन्न कार्यक्रमों से लगाया जाता है जिसके आधार पर किसी दे''ा की कृषि सम्बन्धी क्रियाओं का नियंत्रण एवं विकास हो। 28 जुलाई, 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं– भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका सम्पूर्ण लाभ उठाना, ग्रामीण अवसंरचना को और अधिक दृढ़ बनाना ताकि कृषि सम्बन्धी विकास को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना, कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवारों हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाना, तथा; आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना।

भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के उपरान्त अपनाये गये कृशि नीति के विभिन्न उद्दे''य निम्न लिखित है–

1. कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना।
2. रोजगार का सृजन।
3. वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना।
4. किसानों की आय बढ़ाकर जीवन स्तर ऊंचा करना।
5. औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति।
6. कृषि का यन्त्रीकरण।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जिस पर 60प्रति''ात जनसंख्या निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अं''ादान लगातार घट रहा है जो 17 प्रति''ात से 18 प्रति''ात के बीच है और भारतीय

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

कृषि अर्थवयवस्था के लोगों की आजीविका रोजगार संर्वधन विदे"ाी मुद्रा अर्जन के रूप में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार ने समय–समय पर अपनी कृषि नीति की घोषणा की है भारत में नयी कृषि नीति की घोषणा 2000 में हुयी अर्थात् 18 जुलाई 2000, को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया जिसका लक्ष्य 2005 तक 4 से 4.5 प्रति"ात के बीच कृषि समृद्धि दर प्राप्त करना था इस नीति का उद्दे"य खाद्य सुरक्षा निर्धनता उन्मूलन, संविदात्मक कृषिकों को बढ़ावा देना निजीकरण की भागीदारी को प्रेरित करना इत्यादि था। 26 नवम्बर 2007, को नयी कृषि नीति केन्द्रीय मंत्री शरद पवार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयेागो के अध्यक्ष M.S. Swaminathan की सिफारि"ा पर घोषित की गयी जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य अपनाये गये–

1. कृषि समृद्धि दर 4 से 4.5 प्रति"ात के बीच।
2. कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि।
3. कृषकों की निबल आय में वृद्धि।
4. फसलों, कृषि, प"ाु, मछली, जंगल आदि के सम्बन्ध में बायों सुरक्षा को मजबूत करना।
5. कृषकों के जोखिम प्रबन्धन के उपाय।

उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में निम्न उपाय अपनाये गये–

1. जैव विविधता भूमि एवं जल संरक्षण को लागू करना।
2. बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना।
3. ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जैविक कृषि करना।
4. प्रसंविदा कृषि पर जोर दिया जाये
5. कृषि साख को सस्ता व सुलभ बनाया जाय।
6. ऊवर्रक, बीजों को उचित कीमत पर कृषकों को उपलब्ध कराना
7. बगवानी फसलों पर जोर।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रभावी किया जाय।
9. न्यूनतम समर्थन कीमत को कृषकों के उपलब्ध होने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
10. ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल एवं जैव–विविधता की रक्षा कर सके।
11. विकास के साथ–साथ समानता अर्थात् ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभान्वित कर सके।

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

12. विकास मांग से प्रेरित हो तथा घरेलू बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ–साथ आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण से उत्पन्न कृषि निर्यातों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके।
13. विकास जो तकनीकी रूप से, पर्यावरण सुधार के रूप से तथा आर्थिक रूप से धारणीय हो।

यद्यपि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारि''ा पर बनायी गयी परन्तु कुछ सिफारि''ा सरकार ने नहीं स्वीकार किया इस नीति में किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी पर कोई बात नहीं की गयी। **स्वामीनाथन** आयोग ने किसानों को उनकी लागतों का 50 प्रति''ात सहायता के रूप में तथा 0.0प्रति''ात ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की बात की पर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उपर्युक्त अवहेलनाओं के बावजूद यदि राष्ट्रीय कृषि नीति के रणनीतियॉ ठीक ठंग से क्रियान्वित हुयी तो नि''चत रूप से भारतीय कृषि तथा कृषकों का आर्थिक सुधार होगा।

कृशि क्षेत्र में समस्याएँ :

कृषि क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में पैदावार का अंतर देखा जा रहा है। हरित क्रांति के पाँच दशक बाद भी हरित क्रांति का केंद्र रहे राज्यों और शेष देश के कृषि ज़िलों के बीच चावल और गेहूँ की पैदावार में व्यापक अंतर है। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा के बाहर विभिन्न ज़िलों में उगाए जाने वाले चावल और गेहूँ की पैदावार में अंतर, जोखिम के उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास का अभाव विभिन्न कृषि क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी आम आवश्यकताओं के प्रावधान में भारी असमानता है। कृषि भूमि, फसलों और आदानों (इनपुट्स) के लिये सुव्यवस्थित बाज़ारों के अभाव, श्रम सुधार की धीमी गति तथा शिक्षा की बदतर गुणवत्ता ने कृषि ज़िलों के भीतर एवं उनके बीच समग्र संसाधन गतिशीलता को कम कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और ज़िलों के बीच पैदावार के अंतर को कम करने के लिये आवश्यक विचारों तथा प्रौद्योगिकी की गतिशीलता को भी सीमित कर दिया है। राज्य प्रदत्त विभिन्न इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम मूल्य गारंटीड खरीद योजनाओं ने उत्पादकता के समग्र स्तर और कृषि जोखिम की स्थिति को बदतर किया है, जहाँ यह जल संसाधनों, मृदा, स्वास्थ्य और जलवायु के क्षरण के साथ प्रतिकूल प्रभावों को जन्म दे रहा है। कृषि क्षेत्र की कीमत पर खाद्य सुरक्षा इसका परिणाम केंद्र और राज्य दोनों सरकारी एजेंसियों द्वारा मनमाने एवं परस्पर विरोधी नीतिगत हस्तक्षेपों का दमघोंटू मिश्रण रहा है। विडंबना है कि खाद्य सुरक्षा कृषि क्षेत्र को दाँव पर लगाकर प्राप्त की गई है जो किसानों, परिवारों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों, फर्मों और राज्य जैसे सभी हितधारकों को दायरे में लेता है और ऐसा व्यक्तिगत कल्याण के निम्न स्तर और समग्र जोखिम के उच्च स्तर के साथ किया गया है।

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
***Corresponding author*:** Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

कृषि सुधार हेतु सरकार द्वारा वर्तमान समय में किये गये प्रयास

राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम –

राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई–नाम) के तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जिससे मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) और अन्य कृषि मंडियों के नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाज़ार का निर्माण किया है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कहने को तो वर्चुअल बाजार है, लेकिन यह किसी भी किसान/व्यापारी को देश की किसी भी कृषि मंडी में समान खरीदने व बेचने की सहूलियत देता है।

कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017

कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाये जाने हेतु जारी किया गया। जिसमें ई–व्यापार, सब–यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडारण की घोषणा, मंडी शुल्क एवं कमीशन प्रभार को तर्कसंगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल हैं।

पीएम–किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पीएम– आशा योजना

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ–साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में एक समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' प्रारंभ की थी। नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं–

- मूल्य समर्थन योजना
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

संभावित उपाय

कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो। कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिये। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किये जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए। कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना चाहिये। कृषि अनुसंधान एवं विकास में नूतन प्रयोग करने की आवश्यकता है जिससे सूक्ष्म कृषि, उच्च पोषक और प्रसंस्करण किये जाने वाली किस्में, जलवायु प्रतिरोधक प्रौद्योगिकियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि और बाजार परामर्शों के लिये साइबर कृषि भौतिक प्रणालियाँ विकसित हो सके। कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु–प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 'क्लाइमेट स्मार्ट विलेज' (ब्सपउंजम ैउंतज टपससंहमे) की अवधारण के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिये।

कृषि क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने के लिये एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिये। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सकती है। भारतीय कृषि में आधुनिक उद्यमिता को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये कृषि स्टार्ट–अप्स प्रारंभ करने की आवश्यकता है। स्टार्ट–अप इंडिया योजना के तहत कृषिगत सेवाओं को बढ़ावा दिये जाने से जहाँ एक ओर किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के संदर्भ में प्रोत्साहन प्राप्त होगा, वहीं इससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी। किसी भी क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कार्यवाही की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारों की ही होती है। ज्ञात हो कि कृषि एक राज्य सूची का विषय है इसलिये केंद्र की भूमिका सीमित है। लेकिन जिस प्रकार जी एस टी को लागू करने में केंद्र–राज्यों के मध्य अभूतपूर्व सहयोग देखा गया है। ऐसा ही सहयोग कृषि क्षेत्र में भी अपेक्षित है। कृषि क्षेत्र में भी एकीकृत परिषद का निर्माण करके कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य भावी सम्भावनाएं निम्नवत है–

आय को अधिकतम तथा जोखिम को न्यूनतम करना–

तीन नए कृषि कानून उन व्यापक आर्थिक सुधारों का एक पक्ष मात्र हैं जिनकी आवश्यकता भारतीय कृषि के स्थिरीकरण के लिये पड़ेगी। इन सुधारों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जो कृषक परिवारों को अपना आय अधिकतम करने जबकि कृषि जोखिम के समग्र स्तर को न्यूनतम करने का अवसर दें।

उदारीकृत खेती को बढावा देना– किसानों को अपने खेतों के लिये संसाधनों, भूमि, आदानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों के सर्वोत्तम मिश्रण का निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र किया जाना

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,14(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

चाहिये। राज्य ने बहुत लंबे समय से कृषि परिवारों को नियंत्रित एवं निर्देशित उत्पादन, विपणन और वितरण योजनाओं के अधीन रखा है।

किसानों को गैर–कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की तरह अपनी शर्तों पर और अपनी इच्छा से किसी के भी साथ अनुबंध करने की स्वतंत्रता के साथ कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

कृषि संस्थानों और शासन प्रणालियों में सुधार– प्रमुख नीति क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे लाकर केंद्रीय स्तर पर भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना।

विकेंद्रीकृत प्रणाली का अनुमोदन– ऐसे बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है जो देश भर में किसानों और कृषि संसाधनों की अधिकाधिक गतिशीलता को अनुमति दे। एक वास्तविक विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में असम के किसी किसान को भी पंजाब मॉडल से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पंजाब के किसानों को मिलता है और विलोमतः भी यही स्थिति होगी।

निष्कर्ष

भारत का कृषि–खाद्य क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ यह विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके पास विभिन्न अवसर भी मौजूद हैं। यदि आवश्यक सुधार लागू किये जाते हैं तो ये भारत को अपनी विशाल आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने, अपने लाखों छोटे जोतदारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने और संसाधनों एवं जलवायु पर भारी दबावों को दूर करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही ये सुधार संवहनीय उत्पादकता वृद्धि और एक आधुनिक, कुशल एवं प्रत्यास्थी कृषि खाद्य प्रणाली के निर्माण में सहायता करेंगे जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास और रोज़गार सृजन में योगदान दे सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में गिरावट के बावजूद इसका योगदान 6.1 प्रतिशत से ज्यादा है विश्व में कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत 15 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होने कारण दूसरे स्थान पर है विश्व में मात्र 15 जलवायु क्षेत्र हैं जबकि भारत में 20 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत दुनिया के अग्रणी 15 कृषि उत्पादक निर्यातक देशों में शामिल है। यह सब भारतीय कृषि और किसान को गर्व अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इतना होने के बाद भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का ध्यान रखते हुए भारतीय किसानों भारतीय कृषि की दशा को सुधारने और इसे नई दिशा देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के बजट में ग्रामीण कृषि और उससे जुड़े उद्योगों के लिए आवंटन 24 प्रति''ात बढ़ाकर 187223 करोड़ों रुपए कर दिया गया है। किसानों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। जिसके माध्यम से किसानों की दशा में

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2020). Critical study of agricultural policy and challenges of farmers in India
***International Journal of Economic Perspectives*,*14*(1), 273-279**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
सुधार लाकर उन्हें नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सही नीति बनाई जाए और उसे सही दृष्टि से कार्यान्वित किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- डॉ0 लाल एण्ड लाल (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं वि''लेषण, ि"ाव पब्लि0 इलाहाबाद।
- मिश्रा, एस.के. एवं पुरी, बी.के. (2018) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- भारतीय कृषि की स्थिति (2019) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली।
- कुरूक्षेत्र (अप्रैल 2018) कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
- कृषि वार्षिक रिर्पोट 2019, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- राव,सी.एच.हनुमंथा (2004) एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड परफारमेन्स, इन बिमल जालाल (स) द इंडियन इकोनॉमीः प्राब्लम एंड प्रोस्पेक्ट. पेंगुइन, दिल्ली।

© 2020 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: Dr. Rajesh Kumar Srivastava
Submitted: 27 Aug 2020, Revised: 09 Sep 2020, Accepted: 12 Oct 2020, Published; 30 Nov 2020